VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060

www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS

(आज का विश्लेषण)

(20 January 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरा अंतरिक्ष लॉन्च पैड की स्थापना
- विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक का दावोस में आयोजन
- गांवों में संपत्ति कार्ड जारी करने की स्वामित्व (SVAMITVA) योजना
- MCQ

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे अंतरिक्ष लॉन्च पैड की स्थापना:

चर्चा में क्यों है?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) में तीसरा लॉन्चपैड स्थापित करने को मंजूरी दी है।

- यह नया लॉन्चपैड भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को भविष्य में भारी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) का उपयोग करने के लिए तैयार होने में मदद करेगा, जिसे वह वर्तमान में विकसित कर रहा है।

सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) क्या है?

- सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) वर्तमान में देश का एकमात्र कार्यरत स्पेसपोर्ट है, जहां से अंतरिक्ष यान और उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। यह 9 अक्टूबर, 1971

को 'रोहिणी-125' नामक छोटे साउंडिंग रॉकेट की उड़ान के साथ चालू हुआ था और इसे शुरू में श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज (SHAR) के नाम से जाना जाता था।

- लेकिन सितंबर 2002 में, गणितज्ञ और इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के सम्मान में अंतरिक्ष केंद्र का नाम बदलकर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार (SHAR) कर दिया गया।

श्रीहरिकोटा इसरो के प्रक्षेपणों के लिए एक आदर्श स्थान कैसे बन गया?

- उल्लेखनीय है कि भारत के भविष्य के प्रक्षेपणों के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई ने की थी। उन्होंने अपने साथी वैज्ञानिक एकनाथ वसंत चिटनिस को देश के पूर्वी तट पर एक प्रक्षेपण स्थल की तलाश करने के लिए कहा।
- यह द्वीप, जो लगभग 43,360 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और जिसकी तटरेखा 50 किलोमीटर है। यह द्वीप दक्षिण-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी दोनों मानसून से प्रभावित है, लेकिन भारी बारिश केवल अक्टूबर और नवंबर में होती है। इस प्रकार बाहरी स्थैतिक परीक्षणों और लॉन्चिंग के लिए कई स्पष्ट दिन उपलब्ध हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा का स्थान न केवल भौगोलिक सुविधा का मामला है, बल्कि एक रणनीतिक विकल्प है जो रॉकेट प्रक्षेपण की दक्षता को काफी हद तक बढ़ाता है।
- भूमध्य रेखा से इसकी निकटता विशेष रूप से लाभप्रद है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना सबसे तेज़ है, जिससे इस स्थान से प्रक्षेपित रॉकेट को अतिरिक्त धक्का मिलता है। क्योंकि भूमध्य रेखा के करीब लॉन्च साइट के लिए पृथ्वी के घूमने के कारण प्रदान किए गए वेग का परिमाण लगभग 450 मीटर/सेकंड है, जिससे किसी दिए गए लॉन्च वाहन के लिए पेलोड में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। नतीजतन, इससे प्रक्षेपण अधिक कुशल और लागत प्रभावी हो जाता है।
- भूमध्य रेखा के करीब लॉन्च साइट श्रीहरिकोटा को भूमध्यरेखीय कक्षाओं को लक्षित करने वाले मिशनों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाती है, जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा के साथ संरेखित कक्षाएँ हैं। ऐसी कक्षाओं का उपयोग आमतौर पर संचार और मौसम उपग्रहों के लिए किया जाता है, क्योंकि वे पृथ्वी की सतह का इष्टतम कवरेज प्रदान करते हैं।

- श्रीहरिकोटा की समुद्र से निकटता एक और फायदेमंद कारक है। पानी के ऊपर से रॉकेट लॉन्च करने से खराबी या दुर्घटना की स्थिति में आबादी वाले क्षेत्रों के लिए जोखिम कम हो जाता है।
- साथ ही किसी प्रक्षेपण को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए, भूमि इतनी ठोस होनी चाहिए कि वह प्रक्षेपण के दौरान होने वाले तीव्र कंपन को झेल सके। मजबूत मिट्टी की संरचना और उसके नीचे कठोर चट्टान के साथ, श्रीहरिकोटा इस आवश्यकता को पूरा करता है।
- इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि श्रीहरिकोटा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बेहतर अवस्थिति वाला स्पेसपोर्ट है।

श्रीहरिकोटा का नाम सतीश धवन के नाम पर क्यों रखा गया?

- उल्लेखनीय है कि सतीश धवन एक भारतीय एयरोस्पेस इंजीनियर थे, जिन्हें भारत में प्रायोगिक द्रव गतिकी अनुसंधान के जनक के रूप में जाना जाता था। वे 1972-84 तक इसरो के अध्यक्ष थे। उनके प्रयासों से INSAT, एक दूरसंचार उपग्रह; IRS, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह; और PSLV जैसी परिचालन प्रणालियाँ बनीं, जिसने भारत को अंतरिक्ष-यात्रा करने वाले देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

कुलसेकरपट्टिनम में इसरो के एक नये स्पेसपोर्ट की स्थापना:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम में भारत के लिए दूसरा स्पेसपोर्ट विकसित करने की आधारशिला रखी थी। यह नया प्रस्तावित स्पेसपोर्ट इसरो के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से 700 किलोमीटर से अधिक दूर है और इसे छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में प्रक्षेपित करने के लिए विकसित किया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि जैसे-जैसे भारत अपने अंतरिक्ष प्रयासों का विस्तार कर रहा है, अतिरिक्त लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता महसूस हो रही है। यह और भी अधिक प्रासंगिक है, खासकर छोटे पेलोड (कुछ सौ किलोग्राम) वाले छोटे रॉकेट और ध्रुवीय कक्षाओं की आवश्यकता वाले मिशनों को समायोजित करने के लिए।
- जबकि श्रीहरिकोटा भारी रॉकेट लॉन्च करने में उत्कृष्ट है, छोटे लॉन्च वाहनों, के लिए चुनौतियां पेश करता है, जिन्हें 500 किलोग्राम के उपग्रहों को तैनात करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

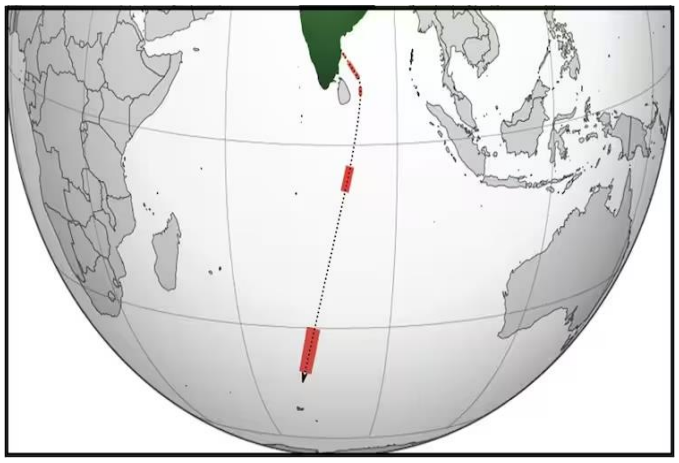

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- साथ ही, श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय कक्षाओं में रॉकेट लॉन्च करते समय, प्रक्षेप पथ को श्रीलंका के ऊपर से उड़ान भरने की आवश्यकता होती है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा होती हैं।
- इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए, SSLV जैसे छोटे रॉकेटों के लिए पेलोड क्षमता को कम करने के लिए ईंधन-गहन युद्धाभ्यास करते हैं।
- कुलसेकरपट्टिनम के भारत के दूसरे अंतरिक्ष पोर्ट के रूप में, इन चुनौतियों का समाधान किया जाना तय है। इस स्थान का रणनीतिक चयन पृथ्वी की घूर्णन दिशा का लाभ उठाता है, जिससे अधिक ईंधन-कुशल प्रक्षेपण की सुविधा मिलती है। इसके अतिरिक्त, इसकी तटीय स्थिति लॉन्च वाहन के मलबे के आबादी वाले क्षेत्रों पर पड़ने के जोखिम को कम करती है, जिससे सुरक्षा प्रोटोकॉल में वृद्धि होती है।
- यह विकास न केवल अंतरिक्ष प्रक्षेपण के लिए भारत की क्षमता का विस्तार है, बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक का दावोस में आयोजन:

चर्चा में क्यों है?

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) 20 से 24 जनवरी तक चलने वाली अपनी पांच दिवसीय 55वीं वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित कर रहा है। यह बैठक "इंटेलिजेंट युग के लिए सहयोग" थीम के तहत आयोजित की जा रही है।
- WEF ने एक बयान में कहा कि इस बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के मद्देनजर इस बात पर विचार किया जाएगा कि विकास को कैसे पुनः गति दी जाए, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग कैसे किया जाए तथा सामाजिक और आर्थिक लचीलेपन को कैसे मजबूत किया जाए।

2025 WTF में शामिल होने वाले प्रमुख लोगों की सूची:

- जिनेवा स्थित WEF ने कहा कि बैठक में 130 से अधिक देशों के लगभग 3,000 नेता भाग लेंगे, जिनमें 350 राजनीतिक नेता भी शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कूल्ज़ और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की दुनिया भर के उन 60 शीर्ष राजनीतिक नेताओं में शामिल होंगे जो दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित करेंगे।
- इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में चार अन्य केंद्रीय मंत्री - सीआर पाटिल, के राम मोहन नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी - और तीन मुख्यमंत्री - देवेंद्र फडणवीस, एन चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी के अलावा अन्य राज्यों के मंत्री और 100 से अधिक सीईओ भी भाग लेंगे।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) क्या है और इसकी शुरुआत किसने की?

- WEF सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए समाज के अग्रणी राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और अन्य नेताओं को शामिल करता है। यह फोरम

'वैश्विक सार्वजनिक हित' में उद्यमिता प्रदर्शित करने के अपने सभी प्रयासों में प्रयासरत है।

- इसकी स्थापना 1971 में एक गैर-लाभकारी फाउंडेशन के रूप में जर्मन प्रोफेसर क्लॉस स्वैब द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- यह जो कुछ भी करता है उसके मूल में नैतिक और बौद्धिक सत्यनिष्ठा होती है। इसकी गतिविधियां "हितधारक पूंजीवादी" सिद्धांत पर स्थापित एक अद्वितीय संस्थागत संस्कृति द्वारा आकार ली गई हैं।

WEF की "हितधारक पूंजीवाद" की अवधारणा क्या है?

- WEF के संस्थापक प्रोफेसर क्लॉस स्वैब के अनुसार, "हितधारक पूंजीवाद", पूंजीवाद का एक रूप है जिसमें कंपनियां न केवल शेयरधारकों के लिए अल्पकालिक लाभ का अनुकूलन करती हैं, बल्कि अपने सभी हितधारकों और बड़े पैमाने पर समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक मूल्य निर्माण की तलाश करती हैं।
- यह विचारधारा मानती है कि एक कंपनी को अपने सभी हितधारकों - कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और उस समुदाय की जिसका वह हिस्सा है - की सेवा करनी चाहिए, न कि केवल अपने शेयरधारकों की।

WEF के वार्षिक दावोस सम्मेलन की सफलताएं:

- अतीत में, इसका उपयोग महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिए एक स्थान के रूप में किया गया है क्योंकि नेता यहां अपने संबंधों में जमी बर्फ तोड़ सकते हैं।
- उत्तर और दक्षिण कोरिया ने दावोस में अपनी पहली मंत्री स्तरीय बैठक की। उसी बैठक में, पूर्वी जर्मन प्रधान मंत्री हंस मोड्रो और जर्मन चांसलर हेल्मुट कोहल ने जर्मन पुनर्मिलन पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की।
- 1992 में, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति डी क्लार्क ने वार्षिक बैठक में नेल्सन मंडेला और मैंगोसुथु बुथेलेज़ी से मुलाकात की, यह दक्षिण अफ्रीका के बाहर उनकी पहली संयुक्त उपस्थिति थी और देश के राजनीतिक परिवर्तन में एक मील का पत्थर था।
- 1998 में, प्रतिभागियों ने इस प्रक्रिया में प्रमुख विकासशील देशों को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। एक विचार यह था कि 20 देशों को शामिल करने के लिए एक निकाय स्थापित किया जाए, जिसमें आधी विकसित अर्थव्यवस्थाएं और दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल हों।
- अंततः G20 बैठक को शिखर सम्मेलन के स्तर तक बढ़ा दिया गया। यह 2008 में तब हुआ था जब अमेरिका ने वैश्विक आर्थिक संकट के प्रभाव को संबोधित करने के लिए वाशिंगटन डीसी में जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी।

- WEF द्वारा 'वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट', 'वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट' और 'वैश्विक जोखिम रिपोर्ट' जैसी रिपोर्ट और सूचकांक भी नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है।

दावोस सम्मेलन की सीमाएं:

- WEF के वार्षिक दावोस सम्मेलन को 'दावोस मैन' भी कहा जाता है, जो वैश्विकवादी अभिजात वर्ग का उपनाम है जिसने 1990 के दशक से दुनिया को आकार दिया है।
- 1989 में बर्लिन की दीवार ढह गई और 1991 में सोवियत संघ ढह गया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका के प्रभुत्व वाले महान शक्ति समूह के भीतर सापेक्ष सद्भाव का दौर आया। आर्थिक मोर्चे पर, तथाकथित वाशिंगटन सर्वसम्मति ने देशों सीमाओं के पार पूंजी, वस्तुओं, सेवाओं और श्रम के मुक्त आवागमन द्वारा चिह्नित एक युग की शुरुआत की। इस युग में लागत अंतर और नीति अनुज्ञा का लाभ उठाने के लिए वैश्विक आर्थिक गतिविधि का पुनर्वितरण भी देखा गया।
- बाजार और दक्षता दुनिया भर में सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के लिए नए मंत्र थे। वैश्विक शासन के नए राजनीतिक विचार इस आर्थिक परिवर्तन से मेल खाते थे। वे इस दृढ़ विश्वास में निहित थे कि विश्व के बढ़ते आर्थिक एकीकरण के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन जैसे सामूहिक खतरों का प्रबंधन करने के लिए संप्रभुता से परे अति-राष्ट्रीय संस्थाएँ आवश्यक थीं।

गांवों में संपत्ति कार्ड जारी करने की स्वामित्व (SVAMITVA) योजना:

चर्चा में क्यों है?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी को कहा कि केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत एक बार देश के सभी गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित हो जाने के बाद, इससे 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक गतिविधि शुरू हो सकती है।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करने के लिए एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब तक गांवों में 2.25 करोड़ लोगों को उनके घरों के लिए कानूनी दस्तावेज मिले हैं।

स्वामित्व (SVAMITVA) योजना क्या है?

- स्वामित्व ***(SVAMITVA:*** *Survey of villages and mapping with improvised technology in village areas)* योजना पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों का दस्तावेजीकरण करना है ताकि वे अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक उद्देश्यों के लिए कर सकें। इस योजना के तहत ड्रोन का उपयोग करके सभी ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जाता है और GIS-आधारित मानचित्र तैयार किया जाता है।
- इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर की थी। यह सर्वेक्षण 2020-2025 की अवधि में चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में किया जाएगा। संपत्ति कार्ड का वितरण 11 अक्टूबर, 2020 को शुरू हुआ।

स्वामित्व योजना का लक्ष्य क्या है?

- ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना।
- ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण।
- संपत्ति कर का निर्धारण, जो सीधे उन राज्यों में ग्राम पंचायतों को मिलेगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या फिर राज्य के खजाने में जोड़ा जाएगा।

- सर्वेक्षण अवसंरचना और GIS मानचित्रों का निर्माण जिसका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा अपने उपयोग के लिए किया जा सकता है।
- GIS मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने में सहायता करना।
- संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करना।

स्वामित्व संपत्ति कार्ड का क्या लाभ है?

- पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, इस योजना से ग्रामीण निवासियों को कई तरह से लाभ मिलता है। सबसे पहले, यह ग्रामीण परिवारों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाता है। 18 जनवरी को पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया।
- यह संपत्ति कर के निर्धारण में मदद करता है, जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों को मिलता है जहां उन्हें ऐसे कर एकत्र करने का अधिकार है।
- यह योजना ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। ग्राम पंचायत स्तर पर सभी संपत्ति रिकॉर्ड और नक्शे उपलब्ध हैं, जिससे गांवों के कराधान, निर्माण परमिट, अतिक्रमण हटाने आदि में मदद मिलती है।

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए हितधारक:

- इस योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित हितधारक शामिल हैं:
  - ➢ नोडल मंत्रालय (पंचायती राज मंत्रालय), भारत सरकार
  - ➢ भारतीय सर्वेक्षण विभाग (प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी)
  - ➢ राज्यों का राजस्व विभाग
  - ➢ राज्यों का पंचायती राज विभाग
  - ➢ स्थानीय जिला प्राधिकरण
  - ➢ संपत्ति का स्वामी
  - ➢ ग्राम पंचायत (GP)
  - ➢ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) - GIS प्रभाग
  - ➢ व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति रखने वाले अन्य विभाग (यदि कोई हो)।

स्वामित्व योजना में कितनी प्रगति हुई है?

- उल्लेखनीय है कि 2020 में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को 9 राज्यों- हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लगभग 1 लाख गांवों में लागू किया गया था।

- इस योजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक देश के सभी 6.62 लाख गांवों को कवर करना था। एक आधिकारिक बयान के अनुसार 3.17 लाख से अधिक गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। 1.53 लाख गांवों में लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।
- यह योजना पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूरी तरह से संतृप्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई केंद्र शासित प्रदेशों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
- पंचायत राज मंत्रालय के अनुसार, कुल 67,000 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण आबादी भूमि का सर्वेक्षण किया गया है, जिसकी कीमत 132 लाख करोड़ रुपये है, जो पहल के आर्थिक महत्व पर जोर देता है।

स्वामित्व योजना को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने की योजना:

- अब सरकार वैश्विक स्तर पर स्वामित्व योजना की सफलता को प्रदर्शित करने की योजना बना रही है।
- मार्च 2025 में, विदेश मंत्रालय के सहयोग से, MoPR ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग 40 प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ भारत में

भूमि प्रशासन पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने की योजना बनाई है। इस कार्यशाला का उद्देश्य दुनिया भर में इसी तरह की पहल के लिए सहयोग को बढ़ावा देते हुए सर्वोत्तम प्रथाओं और उन्नत ड्रोन और GIS प्रौद्योगिकियों को साझा करना है।

- मई 2025 में, मंत्रालय भारत की उपलब्धियों को उजागर करने और मॉडल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए वाशिंगटन में विश्व बैंक भूमि प्रशासन सम्मेलन में भाग लेने की भी योजना बना रहा है।

MCQ

Q.1. चर्चा में रहे 'सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह वर्तमान में देश का एकमात्र कार्यरत स्पेसपोर्ट है, जहां से अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाते हैं।
2. यहां से छोटे लॉन्च वाहनों से प्रक्षेपण करना बेहतर होता है, लेकिन भारी लॉन्च वाहनों, के लिए चुनौतियां पेश आती है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (a)

Q.2. हाल में चर्चा में रहे विश्व आर्थिक मंच द्वारा निम्नलिखित कौन-सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है?

(a) वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट

(b) वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट

(c) वैश्विक जोखिम रिपोर्ट

(d) उपर्युक्त सभी

Ans. (d)

Q.3. चर्चा में रहे इसरो के एक नये स्पेसपोर्ट की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. पिछले वर्ष तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम में भारत के इस नये स्पेसपोर्ट को विकसित करने की आधारशिला रखी गयी थी।
2. इसे नये स्पेसपोर्ट को भारी उपग्रहों को पृथ्वी की भूस्थैतिक कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए विकसित किया जा रहा है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans. (a)

Q.4. चर्चा में रहे विश्व आर्थिक मंच (WEF) 2025 के वार्षिक बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) यह 50वीं वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित कर रहा है।

(b) यह बैठक "इंटेलिजेंट युग के लिए सहयोग" थीम के तहत आयोजित की जा रही है।

(c) यह संयक्त राष्ट्र संघ का एक अंतरसरकारी मंच है, जिसमें दुनिया के 130 देशों से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं।

(d) उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

Ans. (b)

Q.5. चर्चा में रहे 'स्वामित्व योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर की गयी थी।
2. इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों का दस्तावेजीकरण करना है ताकि वे अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक उद्देश्यों के लिए कर सकें।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c)